

सी-मार्ट

चर्चा में क्यों?

9 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तेज़ी से विकास के लिये गाँवों में तैयार उत्पादों को शहरों के मार्केट से जोड़ने की नई पहल करते हुए शहरों में आधुनिक शोरूम की तरह सी-मार्ट स्थापित करने हेतु उद्योग विभाग को निर्देश दिया।

प्रमुख बंदि

- मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों, शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकारों, कुम्भकारों एवं अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का समुचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु इनकी व्यावसायिक ढंग से मार्केटिंग के लिये शहरों में आधुनिक शोरूम की तरह सी-मार्ट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।
- सी-मार्ट की स्थापना से इन सभी वर्गों के उद्यमियों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को निर्देशित करते हुए कहा कि इसके लिये प्रथम चरण में सभी जिला मुख्यालयों में नगर नगिमों की स्थिति में 8 से 10 हजार वर्गफुट तथा नगर पालिकाओं की स्थिति में 6 से 8 हजार वर्गफुट में आधुनिक शोरूम की तरह सी-मार्ट की स्थापना की जाए।
- इसके लिये उन्होंने वर्तमान में उपलब्ध किसी शासकीय भवन का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों में यदि उपयुक्त भवन उपलब्ध न हो, वहाँ कलेक्टर, उद्योग विभाग अथवा वन विभाग को अच्छी लोकेशन में आवश्यकतानुसार भूमि आवंटित किया जाए।
- मुख्यमंत्री ने सी-मार्ट के लिये उपलब्ध भवनों के अपग्रेडेशन अथवा नए भवन के निर्माण हेतु विभिन्न योजनाओं की विभागीय राशि, सी.एस.आई.डी.सी. अथवा लघु वनोपज संघ की राशि उपयोग करने को कहा है।
- मुख्यमंत्री ने 'छत्तीसगढ़ हर्बल्स' के उत्पादों की तरह ही इन वस्तुओं की मार्केटिंग की व्यवस्था लघु वनोपज संघ द्वारा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने जिला कलेक्टरों को महिला समूहों द्वारा निर्मित एवं अन्य सभी पारंपरिक उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रैंडिंग एवं मार्केटिंग की व्यवस्था हेतु प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ से समन्वय करने को कहा है।